

इंजीनियर बना नशातस्कर, 4 करोड़ गांजा और 36 लाख नगद मिले
बैंगलुरु, ईमएस। इंजीनियर अब इग्रेज बेचने का काम कर रहा था। पुलिस का कहना है कि ये आईटी कंपनियों में काम करते वाले लोगों को हाइडोगांजा सलाई करता था। पुलिस ने इसे 3.5 किलो गांजा बरामद किया है। इस गांजे की मित लगभग 4 करोड़ रुपये बरता रही है। साथ ही, पुलिस को इसके पास से 36 लाख रुपये कैश भी मिले हैं।

राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय

प्रकृति का ऐसा कहर कि चारों ओर मचा कोहराम

ओले, बाढ़ और आंधी से उजड़ा इस्लामाबाद

उखड़े पेड़ तो राहते हुए बंद, बारिश ने दी गर्मी से राहत लेकिन बिजली हुई गुल



ओले की मार से बर्बाद हुए वाहन
सोशल मीडिया पर कई वीडियो आए हैं, जिसमें दिख रहा है कि डर्जनों गाड़ियां ओले की मार से बाढ़ लोगों ने अपने घरीं और ओले ने इस्लामाबाद को ठान-नहस कर दिया। गाड़ियों के शीशे चकानारू, सोलर पैनल बर्बाद, पेड़ उखड़े गए और कई इलाकों में बाढ़ ने कोहराम मचा दिया।

आगरा, ईमएस। एकत्रित आगरा इमारतों में एक नियुआनियाई महिला पर्टटक के साथ कथित छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस ने मौत की विवासी मिजाज नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह घटना तब हुई थी। महिला द्वारा पर्यटक थाना पुलिस में शिकायत दर्ज की गई, जिसके बाद ताज सुरक्षा के सहायता परिवर्तन आयुक्त रेपर अद्वारा के विवासी में सीसीटीवी पूर्फुज डेक्टर के मिजाज की पहचान कर रिपर तकिया को गिरफ्तार किया गया। अद्वितीयों के अनुसार, आरोपी मिजाज भी आगरा किला देखने की आथा और तभी आरोपी ने महिला पर्टटक को अनुचित तरीके से मुआ।

सेना का जवान गिरफ्तार

जालंधर, ईमएस। जालंधर के एक यूट्यूबर के घर पर बीते महीने हथगोला फैंडों की घटना के मामले में सेना के एक जवान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि जिसके बाद ताज के जवान सुरक्षायांसिंह को एक आरोपी को हथगोला फैंडों के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यूट्यूबर रोजर संघ के आवास पर 15-16 मार्च की दिन अपनी रात को एक हथगोला फैंडों के आरोपी को हथगोला फैंडों के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

यूट्यूबर रोजर संघ के आवास पर 15-16 मार्च की दिन अपनी रात को एक हथगोला फैंडों के आरोपी को हथगोला फैंडों के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

जिसके बाद मैं जेना अधिकारियों को अवगत किया गया है।

भारत दौरे पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेस

नई दिल्ली, ईमएस। अमेरिकी

उपराष्ट्रपति जेडी वेस अपनी पत्नी

जूडी और बच्चों के साथ 18 अप्रैल

को भारत दौरे पर आ रहे हैं।

यह दौरा

18 से 24 अप्रैल तक चलेगा, जिसके

बाद दैस दंती टिट्टों की यात्रा पर

रवाणा होने वाले हैं। भारत में अपने

प्रवास के दौरान देंगे प्रधानमंत्री नेटवर्क

मेंदों से मुलाकात करने और

व्यापारिक टैरेंज जैसे अमेरिकी

सेकेड लेडी हैं। उनका आठतारीफ़ और उत्तराधिकारी अमेरिकी व्यापारिक और संस्कृतिकी दृष्टिकोण से भी

काफी अहम है। सूर्यों के मुताबिक,

वेस परिवर्त आगरा में ताजमहल का

दीदार करेगा।

हवाई हमले में एक व्यक्ति की मौत

सना, ईमएस। यमन की राजधानी सना में हुए स्कूदिध अमेरिकी हवाई हमलों में कम से कम एक व्यक्ति की

मौत हुई है। यह दायरा यमन में द्वितीय

हूनीविद्युहियों के द्वितीय

प्रयोग के दौरान हो रही है।

यमन की राजधानी

सना में हुए स्कूदिध अमेरिकी हवाई

हमलों के दौरान करने आरोपी ने अमेरिकी

हवाई हमले के दौरान देंगे

प्रयोग के दौरान हो रही है।

यमन की राजधानी

सना में हुए स्कूदिध अमेरिकी हवाई

हमलों के दौरान करने आरोपी ने अमेरिकी

हवाई हमले के दौरान देंगे

प्रयोग के दौरान हो रही है।

यमन की राजधानी

सना में हुए स्कूदिध अमेरिकी हवाई

हमलों के दौरान करने आरोपी ने अमेरिकी

हवाई हमले के दौरान देंगे

प्रयोग के दौरान हो रही है।

यमन की राजधानी

सना में हुए स्कूदिध अमेरिकी हवाई

हमलों के दौरान करने आरोपी ने अमेरिकी

हवाई हमले के दौरान देंगे

प्रयोग के दौरान हो रही है।

यमन की राजधानी

सना में हुए स्कूदिध अमेरिकी हवाई

हमलों के दौरान करने आरोपी ने अमेरिकी

हवाई हमले के दौरान देंगे

प्रयोग के दौरान हो रही है।

यमन की राजधानी

सना में हुए स्कूदिध अमेरिकी हवाई

हमलों के दौरान करने आरोपी ने अमेरिकी

हवाई हमले के दौरान देंगे

प्रयोग के दौरान हो रही है।

यमन की राजधानी

सना में हुए स्कूदिध अमेरिकी हवाई

हमलों के दौरान करने आरोपी ने अमेरिकी

हवाई हमले के दौरान देंगे

प्रयोग के दौरान हो रही है।

यमन की राजधानी

सना में हुए स्कूदिध अमेरिकी हवाई

हमलों के दौरान करने आरोपी ने अमेरिकी

हवाई हमले के दौरान देंगे

प्रयोग के दौरान हो रही है।

यमन की राजधानी

सना में हुए स्कूदिध अमेरिकी हवाई

हमलों के दौरान करने आरोपी ने अमेरिकी

हवाई हमले के दौरान देंगे

प्रयोग के दौरान हो रही है।

यमन की राजधानी

सना में हुए स्कूदिध अमेरिकी हवाई

हमलों के दौरान करने आरोपी ने अमेरिकी

हवाई हमले के दौरान देंगे

प्रयोग के दौरान हो रही है।

यमन की राजधानी

सना में हुए स्कूदिध अमेरिकी हवाई

हमलों के दौरान करने आरोपी ने अमेरिकी

हवाई हमले के दौरान देंगे

प्रयोग के दौरान हो रही है।

यमन की राजधानी

सना में हुए स्कूदिध अमेरिकी हवाई

हमलों के दौरान करने आरोपी ने अमेरिकी

हवाई हमले के दौरान देंगे

प्रयोग के दौरान हो रही है।

यमन की राजधानी

सना में हुए स्कूदिध अमेरिकी हवाई

हमलों के दौरान करने आरोपी ने अमेरिकी

हवाई हमले के दौरान देंगे

प्रयोग के दौरान हो रही है।

यमन की राजधानी

सना में हुए स्कूदिध अमेरिकी हवाई

हमलों के दौरान करने आरोपी ने अमेरिकी

बाढ़ एवं अतिवृष्टि की पूर्व तैयारियों के संबंधमें बैठक 21को

खरगोन, ईएमएस। बाढ़ एवं अतिवृष्टि की स्थिति से निपटने एवं पूर्व तैयारियों के संबंध में कलेक्टर सुश्री भव्या मितल की अध्यक्षता में 21 अप्रैल को शाम 04 बजे कलेक्टर सभाकाश में समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में जिला सुव्यालय पर पदस्थ संबंधित अधिकारी बाढ़, आपदा एवं अतिवृष्टि से निपटने के लिए आवश्यक पूर्व तैयारियों के संबंध में कार्य/कार्यालय से संबंधित आवश्यक जानकारी लेकर उपस्थित रहेंगे।

संपादकीय

सुप्रीम कोर्ट पहुंची हिंदू-मुस्लिम की लड़ाई

केंद्र | सरकार द्वारा जो वक्फ अधिनियम 2025 संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया है इस विधेयक को रास्तपि की मंजरी भी मिल गई है। यह लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू-मुस्लिम की लड़ाई अब आर-पार की रास्तपि में पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को लेकर 70 से अधिक याचिकाओं पर सुनाई मुख्य न्यायाधीश और दो जजों की खंडपीठ में शुरू हो गई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को अंतरिम आदेश जारी कर सकती है। ऐसी संभावना जारी जा रही है। केंद्र सरकार मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है। उनकी दान की हुई संपत्ति पर सरकार हक जाना चाहती है। वक्फ संपत्ति पर सरकार अपने हिसाब से नियंत्रण करना चाहती है। मुसलमानों के धार्मिक क्रिया-कलापों पर शासन हस्तक्षेप कर मुसलमानों पर अंकुश लगाना चाहती है। यह संशोधन से स्पष्ट है। इसकी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया देशराघ के मुसलमानों के साथ-साथ अन्य अल्पसंख्यक समुदायों में भी हो रही है।

पिछले 11 वर्षों से मुसलमानों के साथ में जो भेदभाव केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है, वक्फ अधिनियम के रूप में वह सामने आ गया है। अभी तक मुसलमानों को किया जाना चाहिए और विरोध कर रहे हैं। इस अधिनियम ने उन सब को एक जुट करके लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जिस तरह से वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की नियुक्ति की जा रही है। क्या ऐसी ही नियुक्ति अन्य गैर मुस्लिम बोर्ड में की जा सकती है। हिंदू मंदिरों और हिंदू बोर्ड में गैर हिंदुओं की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया। 13 वीं, 14वीं शताब्दी और सैकड़ों वर्ष पुरानी मस्जिदें और धार्मिक स्थल हैं उसके रजिस्ट्रेशन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया। केंद्र सरकार के सालिसिटर जनरल तुशर मेहता कोर्ट में जबाब नहीं दे पाए। संविधान में अल्पसंख्यकों को तथा सभी नागरिकों को अपने धर्म को पालन करने की जो स्वतंत्रता दी गई है। नागरिक अधिकार भी इस संशोधन में बाधित हो रहे हैं। 5 साल का प्रैविटर नागरिक अधिनियम ही सामने आ गया है। इस तरह के सवालों का जवाब कालिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में नहीं दे पाए। पिछले कुछ वर्षों से न्यायपालिका के ऊपर वह अपेक्षित लगते रहे हैं, वह सरकार के दबाव पर काम करती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को कसीटी पर काम करना है। संविधान में बिना संशोधन किए उपर जिस तरह से वक्फ बिल के द्वारा करारें मुसलमानों के धार्मिक क्रियाकालापन और इवादत करने के ऊपर जिसका अधिनियम और इवादत करने के लिए एक बालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपेक्षित लगते रहे हैं। अब अपेक्षित लगते रहे हैं। यह अपेक्षित हो गया है। निश्चित रूप से संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट नियंत्रण देने में आनाकासा करती है। ऐसी स्थिति में यह माना जाएगा की संवैधानिक व्यवस्था की आड़ में असंवैधानिक कार्यों को न्यायपालिका संरक्षित और बढ़ावा देने का काम कर रही है।

- सनत जैन

राज काज

दिल्ली के मुख्यमंत्री परिचयाओं में

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं। रेखा गुप्ता पर्दी-लिपियां न्याय के महिला हैं। छात्र बोता भी रही हैं। जब से वह मुख्यमंत्री बनी हैं। अधिकारियों की निर्देश भी देते हैं। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने वित्त विभाग के एक फोटो जारी की है जिसमें मुख्यमंत्री के पाति मुकेश गुप्ता अधिकारियों की बैठक में भगवते रहे हैं। अभी तक देश में पंच, सरपर परिचय विधायिका को आवश्यक लिये जाते हैं। अभी तक देश में अविश्वास बढ़ रहा था, वह अविश्वास खत्म होगा। न्यायपालिका और संविधान के प्रति एक बार फिर सभी का विश्वास जागृत होगा। ऐसी आशा सुप्रीम कोर्ट से की जा सकती है।

- सनत जैन

सुप्रीम कोर्ट पहुंची हिंदू-मुस्लिम की लड़ाई

केंद्र | सरकार द्वारा जो वक्फ अधिनियम 2025 संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया है इस विधेयक को रास्तपि में पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू-मुस्लिम की लड़ाई अब आर-पार की रास्तपि में पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को लेकर 70 से अधिक याचिकाओं पर सुनाई मुख्य न्यायाधीश और दो जजों की खंडपीठ में शुरू हो गई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को अंतरिम आदेश जारी कर सकती है। ऐसी संभावना जारी रही है। केंद्र सरकार मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है। उनकी दान की हुई संपत्ति पर सरकार हक जाना चाहती है। वक्फ संपत्ति पर सरकार अपने हिसाब से नियंत्रण करना चाहती है।

रास्तपि की मंजरी भी मिल गई है। यह लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को लेकर 70 से अधिक याचिकाओं पर सुनाई मुख्य न्यायाधीश और दो जजों की खंडपीठ में शुरू हो गई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को अंतरिम आदेश जारी कर सकती है। ऐसी संभावना जारी रही है। केंद्र सरकार मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है। उनकी दान की हुई संपत्ति पर सरकार हक जाना चाहती है। वक्फ संपत्ति पर सरकार अपने हिसाब से नियंत्रण करना चाहती है।

पिछले 11 वर्षों से मुसलमानों के साथ में जो भेदभाव केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है, वक्फ अधिनियम के रूप में वह सामने आ गया है। अभी तक मुसलमानों को किया जाना चाहिए और विरोध कर रहे हैं। इस अधिनियम ने उन सब को एक जुट करके लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जिस तरह से वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की नियुक्ति की जा रही है। क्या ऐसी ही नियुक्ति अन्य गैर मुस्लिम बोर्ड में की जा सकती है। हिंदू मंदिरों और हिंदू बोर्ड में गैर हिंदुओं की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया। 13 वीं, 14वीं शताब्दी और सैकड़ों वर्ष पुरानी मस्जिदें और धार्मिक स्थल हैं उसके रजिस्ट्रेशन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया। केंद्र सरकार के सालिसिटर जनरल तुशर मेहता कोर्ट में जबाब नहीं दे पाए। संविधान में अल्पसंख्यकों को तथा सभी नागरिकों को अपने धर्म को पालन करने की जो स्वतंत्रता दी गई है। नागरिक अधिकार भी इस संशोधन में बाधित हो रहे हैं। 5 साल का प्रैविटर नागरिक अधिनियम ही सामने आ गया है। इस तरह के सवालों का जवाब जवाबदार जनरल सुप्रीम कोर्ट में नहीं दे पाए। पिछले कुछ वर्षों से न्यायपालिका के ऊपर वह अपेक्षित लगते रहे हैं, वह सरकार के दबाव पर काम करती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को संवैधानिक व्यवस्था की ऊपर जिसका अधिनियम और इवादत करने के लिए एक बालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपेक्षित हो रहे हैं। अब भी अपेक्षित हो रहे हैं। यह अपेक्षित हो गया है। निश्चित रूप से संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट नियंत्रण देने में आनाकासा करती है। ऐसी स्थिति में यह माना जाएगा की संवैधानिक व्यवस्था की आड़ में असंवैधानिक कार्यों को न्यायपालिका संरक्षित और बढ़ावा देने का काम कर रही है।

पिछले 11 वर्षों से मुसलमानों के साथ में जो भेदभाव केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है, वक्फ अपेक्षित हो रहे हैं। वह सरकार के दबाव पर काम करती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को कसीटी पर काम करना है। संविधान में बिना संशोधन किए उपर जिस तरह से वक्फ बिल के द्वारा करारें मुसलमानों के धार्मिक क्रियाकालापन और इवादत करने के ऊपर जिसका अधिनियम और इवादत करने के लिए एक बालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपेक्षित हो रहे हैं। अब भी अपेक्षित हो रहे हैं। यह अपेक्षित हो गया है। निश्चित रूप से संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट नियंत्रण देने में आनाकासा करती है। ऐसी स्थिति में यह माना जाएगा की संवैधानिक व्यवस्था की आड़ में असंवैधानिक कार्यों को न्यायपालिका संरक्षित और बढ़ावा देने का काम कर रही है।

पिछले 11 वर्षों से मुसलमानों के साथ में जो भेदभाव केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है, वक्फ अपेक्षित हो रहे हैं। वह सरकार के दबाव पर काम करती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को कसीटी पर काम करना है। संविधान में बिना संशोधन किए उपर जिस तरह से वक्फ बिल के द्वारा करारें मुसलमानों के धार्मिक क्रियाकालापन और इवादत करने के ऊपर जिसका अधिनियम और इवादत करने के लिए एक बालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपेक्षित हो रहे हैं। अब भी अपेक्षित हो रहे हैं। यह अपेक्षित हो गया है। निश्चित रूप से संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट नियंत्रण देने में आनाकासा करती है। ऐसी स्थिति में यह माना जाएगा की संवैधानिक व्यवस्था की आड़ में असंवैधानिक कार्यों को न्यायपालिका संरक्षित और बढ़

